

हिन्दी दैनिक

उपभोक्ता की दुनिया

श्रावस्ती से प्रकाशित

वर्ष : 21 अंक : 25

श्रावस्ती, मंगलवार 01 जुलाई 2025

पृष्ठ : 4

मूल्य : 1 रुपया

मणिपुर में चार लोगों की गोली मारकर हत्या

मणिपुर (एजेन्सी)। मणिपुर हिसारूमणिपुर अंदर ही अंदर सुलग रहा है। जहां एक तरफ अधिकारी दावा कर रहे हैं कि फरवरी में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से मणिपुर में हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु और घायल होने की संख्या कम हुई है और नशीले पदार्थों की जड़ों में वृद्धि हुई है। मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और अर्धसैनिक इकाइयों सहित सुरक्षा बल मई 2023 में हिंसा के दौरान पुलिस शास्त्रागार से लूटे गए हजारों हथियारों को बरामद करने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरह एक तस्वीर ऐसी है जहां अभी भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। ताजा खबर मणिपुर के चुराचांदपुर से आ रही हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में अज्ञात बंदूक ारियों ने 60 वर्षीय महिला सहित कम से कम चार लोगों की सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिाकारी ने बताया कि घात लगाकर यह हमला मोंगजांग गांव के पास दोपहर दो बजे के आसपास हुआ जब पीड़ित एक कार में यात्रा कर रहे थे।

विधायक टी राजा ने भाजपा से दिशा इस्तीफा

तेलंगाना (एजेन्सी)। भाजपा को झटका देते हुए तेलंगाना के गंशामहल से विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राज्य नेतृत्व के लिए चल रही खींचतान पर नाराजगी जताते हुए राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजा। अपने पत्र में राजा सिंह ने स्पष्ट किया कि भले ही वह भाजपा से अलग हो रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व विचारधारा और धर्म की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अपरिवर्तित है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी अधिक मजबूती से खड़ा रहूंगा।

इससे पहले राजा सिंह ने भाजपा नेतृत्व से उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने की अपील की थी। राजा सिंह ने एक वीडियो में कहा कि पार्टी के कई कार्यक्रमों उन्हें फोन कर रहे हैं और उन्हें अध्यक्ष पद पर देखने की इच्छा जता रहे हैं।

अब मिजोरम में गुँजेगी रेल की सीटी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेल उन स्थलों तक भी पहुँची है जहां रेलवे का सपना तो बहुत पहले देखा गया लेकिन उसे पूरा करने की दिशा में पहले की सरकारों ने कोई बड़े कदम नहीं उठाये थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में चिनाव पुल का उद्घाटन किया था जिससे कश्मीर घाटी का राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने का सपना पूरा हुआ। अब सुदूर पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए निर्धारित 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग रेल लाइन भौगोलिक और साजोसामान से जुड़ी चुनौतियों को पार करते हुए बन कर तैयार हो चुकी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के एक अधिकारी ने कहा है, “रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएसआर) की मंजूरी के साथ यह लाइन तैयार है।

राजनीति का इतना तापमान

असहनीय : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली (एजेन्सी)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज का राजनीतिक माहौल भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के समय में राजनीति का माहौल और उसका तापमान, दोनों ही हमारे लोकतंत्र और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हैं। यह हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति से भी मेल नहीं खाता है। राजनीति में आप अलग-अलग दलों में हो सकते हैं और इसमें भी बदलाव होता रहता है कृ और बड़ा बदलाव होता है।

बरेली के आईवीआरआई में राष्ट्रपति ने मेधावियों को दिए पदक व उपाधि, कहा- पशु कल्याण की भावना से करें कार्य



बरेली (एजेन्सी)। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान (आईवीआरआई) के 11वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्लेग महामारी के बाद अस्तित्व में आए इस विश्वस्तरीय संस्थान ने पशु संबंधी बीमारियों के निदान से लेकर जैव सुरक्षा तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां से डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को संदेश

दिया है कि वह सर्व भवन्तु सुखिनरु सर्वे संतु निरामयारु की भावना से सबके कल्याण की दिशा में काम करें। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति ने छात्र-छात्राओं से कहा कि प्रकृति का पारिस्थितिकी चक्र बनाए रखने के लिए पशुओं व जीव जंतुओं का निरोग होना आवश्यक है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ ही वर्षों में गिद्ध विलुप्त से हो गए हैं जबकि

देवताओं का संवाद होता है, इसलिए उनकी बीमारियों के निदान के लिए नए प्रयोग होते रहने चाहिए। कहा कि वह खुद जिस परिवेश से आई हैं, वहां पशुओं के बिना किसान तरक्की नहीं कर सकते। डिग्री लेने वालों में छात्राओं की ज्यादा संख्या देखाकर राष्ट्रपति ने खुशी जताई। कहा कि प्राचीन काल से घरों में माताएं-बहनें ही पशुओं की सेवा

मानव, प्रकृति व पशु सभी एकदूसरे पर आधारित हैं। इसी तरह अन्य जीवों की माँ जूद गी आवश्यक है। नए पशु चिकित्सक और वैज्ञानिक इस दिशा में काम करें। उन्होंने वेदों का जिक्र करते हुए कहा कि पशुओं से

करती आई हैं। इसलिए वह यकीन करती हैं कि महिलाएं पशु रोगों के निदान में ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। जब आप लोगों ने पशु सेवा का यह जरिया चुन लिया है तो सभी के कल्याण के लिए काम कीजिए। प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि वैज्ञानिक व चिकित्सकों को चाहिए कि वह गांवों में जाकर धरातल पर पशुओं से संबंधित रोगों के निदान पर काम करें। गांव में किसान व महिलाएं आपको इस बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, तभी आप अच्छा उपचार कर सकेंगे। यह भी कहा कि आप लोग पशु चिकित्सा व शोध के लिए सरकार से आर्थिक मदद ले सकते हैं, ऐसा करके आप कृषि व पशु संरक्षण को बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों को मेडल नहीं मिला है, वह निराश न हों और इसके लिए अभी से ज्यादा मेहनत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में मौजूद छात्र-छात्राओं से कहा कि पशुओं की मूक आवाज और

समस्या आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपके उपचार करने से पशुओं को नया जीवन मिलेगा। इस संस्थान के शिक्षकों की वर्षों की साधना के प्रतिफल के रूप में आप लोगों को यह डिग्री मिली है। अपेक्षा है कि अपने ज्ञान से पशु बीमारियों का निदान, टीकाकरण आदि पर जोर दें। उन्होंने कोरोना के दौर में आईवीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि पशु चिकित्सा से इतर मानव जीवन बचाने को दो लाख से ज्यादा परीक्षण इस संस्थान ने किए। लंपी के दूसरे चरण में जब गोवंश चपेट में आने लगे तो भी आईवीआरआई ने उल्लेखनीय कार्य किया। ाष्ट्रपति करीब साढ़े दस बजे वायु सेना के विशेष वायुयान से बरेली पहुंचीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह उनके साथ ही आए थे। हवाई अड्डे पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य अतिथियों ने उनका स्वागत किया।

सीएम योगी ने आईवीआरआई के शोधकर्ताओं की सराहना की

बरेली (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के 11वें दीक्षांत समारोह में शोध कर्ताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान की 136 वर्षों की साधना पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। आप जैसे वैज्ञानिक मूक पशुओं की आवाज बनते हैं। आप सभी का शोध और सेवा समाज को एक नई दिशा देता है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने मेधावियों को पदक और उपाधियां वितरित कीं। मुख्यमंत्री ने बरेली को भारत की पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र

प्राचीनकाल में पांचाल देश के रूप में विख्यात था। यहां सात प्राचीन नाथ मंदिर हैं, जिन्हें ‘नाथ कॉरिडोर’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाबा अलखनाथ, वनखंडीनाथ, त्रिवटीनाथ, तपेश्वरनाथ, मढ़ीनाथ, धोपेश्वरनाथ और श्री पशुपातिनाथ मंदिर बरेली की पहचान हैं। उन्होंने कहा कि जहां मंदिरों की शृंखला बरेली को आध्यात्मिक पहचान देती है, वहीं आईवीआरआई ने इसे आधुनिक वैज्ञानिक पहचान प्रदान की है। सीएम योगी ने कहा कि आईवीआरआई न केवल पशुधन बल्कि हर जीव-जंतु के लिए जीवन रक्षक सेवा का केंद्र बना है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में दौरान जब जांच एक चुनौती बनी हुई थी, तब आईवीआरआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर दो

लाख से अधिक कोविड जांच करवाईं। सीएम योगी ने कहा कि आईवीआरआई की प्रतिबद्धता यह दिखाता है कि इसकी भूमिका केवल पशु चिकित्सा तक सीमित नहीं, बल्कि वह मानव जीवन रक्षा में भी अग्रणी रही है। सीएम योगी ने कहा कि लंपी स्कैन डिजीज की दूसरी लहर के दौरान जब गोवंश बुरी तरह प्रभावित हुआ, तब आईवीआरआई द्वारा विकसित टीके ने उत्तर प्रदेश को संक्रमण से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को उनके मूक प्राणियों की सेवा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी खोजों ने किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। पशुधन की उन्नत नस्ल देकर अन्नदाता को सशक्त किया है। आईवीआरआई



की 136 वर्षों की यह साधना पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन आपको जीवन का एक नया अध्याय है। यह केवल डिग्री नहीं, बल्कि समाज को आपकी सेवा समर्पित करने

शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अखिलेश यादव, हिंदुओं को लड़ाकर छक रहे हैं भंडारा : महंत राजू दास



लखनऊ (एजेन्सी) उत्तर प्रदेश के इटावा प्रकरण के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रि모 अखिलेश यादव का विवादस्पद बयान आया है। उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम) को निशाना बनाते हुए कहा कहने के एवज में पैसे लेने को लेकर निंदनीय टिप्पणी की है। इसी कड़ी में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश को यह दिक्कत नहीं है कि कथा कहने वह उनके घर पर नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि दिक्कत ये है कि वह हिंदुओं को एक कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को आपस में लड़ाने

का कार्य किया है वह घृणित है। वे खुद को यादवों और पंडितों को आपस में लड़ाकर दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं और खुद एक पंडित जी के घर जाकर भंडारा छक रहे थे। दूसरी ओर, बागेश्वर सरकार के ऊपर टिप्पणी करके उन्होंने एक प्रकार से टारगेट किया है। उन्होंने बागेश्वर सरकार को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वह हिंदुत्व पर काम करते हैं। वह सनातन पर कार्य करते हैं और छूआ-छूत व भेदभाव को कम करके हिंदुओं को नहीं है कि कथा कहने वह उनके घर पर नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि दिक्कत ये है कि वह हिंदुओं को एक कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को आपस में लड़ाने

तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 9२ मजदूरों की मौत और ३४ जख्मी

संगारेड्डी (एजेन्सी) तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिफ़क्टर यूनिट में विस्फोट हो गया। घटना में 12 मजदूरों की मौत हो गई, 34 लोग जख्मी हैं। हादसा पाशमिलारम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह 8:15 बजे से 9.30 बजे के बीच हुआ। राज्य के श्रम मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी ने कहा अबतक 4 शव बरामद हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अब और कोई मौत नहीं होगी। आईजी वी

सत्यनारायण ने बताया कि घटना के दौरान फैक्ट्री में 150 लोग थे, जहां ब्लास्ट हुआ वहां 90 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं एनडीआरएफ, डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रिफ़क्टर में तेजी से श्रम मंत्री जी विवेक वेंकटस्वामी ने केमिकल रिफ़क्शन होने से ब्लास्ट की संभावना जताई गई है। इधर, पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने को घटना पर दुख जताया।

पीएम नेशनल रिलीफ़ फंड से मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की मदद की घोषणा की। एक मजदूर ने बताया कि मैं सुबह 7 बजे नाइट शिफ्ट पूरी करके बाहर निकला था। सुबह की शिफ्ट का स्टॉफ़ अंदर आ चुका था। ९ माका करीब करीब 8 बजे हुआ। मैं शिफ्ट में मोबाइल जमा हो जाता है, इस वजह अंदर काम कर रहे लोगों की कोई खबर नहीं मिल पाई। एक मजदूर की महिला परिजन ने बताया कि उनके परिवार के चार लोग फैक्ट्री

में काम करते हैं। इनमें उनका बेटा, दामाद, जेट और देवर शामिल हैं। इनमें से तीन सुबह की शिफ्ट में थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि वहां काम कर रहे मजदूर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। विस्फोट की वजह से रिफ़क्टर यूनिट तबाह हो गई है। कंपनी के एक कर्मचारी ने बताया कि अति प्रा्दतर मजदूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक शिफ्ट में 60 से ज्यादा मजदूर और 40

अन्य लोगों का स्टॉफ़ काम करता है। सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल पाउडर बनाती है। यह साल 1989 से माइक्रोक्रीस्टललाइन सेलुलोज (एमसीसी) बना रही है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इसमें कोई गंध या स्वाद नहीं होता है।एमसीसी का उपयोग दवा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। सिगाची इंडस्ट्रीज की हैदराबाद समेत पूरे देश में पांच फ़ैक्ट्रियां हैं। कंपनी के प्रोडक्ट 65 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं।

सिगाची फार्मा कंपनी में विस्फोट, 12 की मौत, पीएम मोदी ने किया आर्थिक मदद का एलान

तेलंगाना (एजेन्सी)। तेलंगाना के संगारेड्डी में सोमवार को एक फार्मा प्लांट में हुए संधिग्ध विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 34 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पशाम्यलारम औद्योगिक एस्टेट में सिगाची फार्मा कंपनी में जहां विस्फोट हुआ, वहां कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया,हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उनका इलाज जारी है। उनकी हालत के बारे में तत्काल पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बचाव अभियान अभी भी जारी है। आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को लगाया गया। मल्टी जोन II के महानिरीक्षक वी सत्यनारायण ने बताया कि पशाम्यलारम में रासायनिक उत्पादन फैक्ट्री सिगाची फार्मा में विस्फोट हुआ। यह घटना सुबह 8रु15 से 9:35 बजे के बीच हुई। घटना में कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 34 अन्य घायल हैं। छह शव बरामद किए गए हैं। चंदा नगर में इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई।

हम 20 मिनट में ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल 10 दमकल गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मौत पर जताया। उन्होंने कहा, घटना से दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

जानवर ‘जीवन धन है’, ‘पशु शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

बरेली (एजेन्सी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जानवरों के लिये ‘पशु’ शब्द का इस्तेमाल करना ‘ठीक नहीं’ है।र मुर्मू ने जानवरों को ‘जीवन धन करार दिया। राष्ट्रपति ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के 11वें दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा, “जानवरों के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए ‘पशु’ शब्द ठीक नहीं लगता। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते।” उन्होंने कहा, “हमारी संस्कृति जीव-जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। राष्ट्रपति ने कहा, पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि-मुनियों का संवाद होता है। यह मान्यता भी इस सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में हैं।” मुर्मू ने जैव विविधता के महत्व को दर्शाते हुए कहा कि आईवीआरआई जैसी संस्थाओं से अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। उन्होंने अपने बचपन की किस्सों का उदाहरण देते हुए कहा, “हम जब छोटे थे तब बहुत सारे गिद्ध थे, लेकिन आज गिद्ध लुप्त हो गए हैं। मुझे लगता है कि गिद्ध के विलुप्त होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली रासायनिक दवाओं की भूमिका है। बहुत सारे कारणों में यह भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गिद्धों के संरक्षण की दिशा में सहायनीय कदम है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए वैज्ञानिकों के प्रति आभार जताया और कहा, “कई प्रजातियां विलुप्त हो रहीं हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आईवीआरआई जैसे संस्थाओं से अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। मुर्मू ने समारोह में मौजूद विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, “आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर काफी गर्व महसूस कर रही हूं। बेटियां अन्य क्षेत्रों की तरफ पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं, यह बहुत ही शुभ संकेत है। मुर्मू ने महिलाओं से आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि गांवों में पशुओं, गायों की सेवा मां-बहनें करती थीं, क्योंकि माता-बहनों से उनका जुड़ाव है।

मराठी के ऊपर हिंदी थोपे जाने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएगी : राज ठाकरे

मुंबई (एजेन्सी) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को कहा कि हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, लेकिन यह अन्य राज्यों पर थोपी जाने वाली राष्ट्रीय भाषा नहीं है तथा इसे प्राचीन भाषा



मराठी से ऊपर रखने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनसे और उद्भव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए तीसरी भाषा के रूप में ‘हिंदी को थोपने’श का विरोध करने में सबसे आगे रही है। महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक हिंदी भाषा को शामिल करने के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच रविवार को राज्य सरकार ने ‘त्रि-भाषा नीति पर सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकारी आदेश को वापस ले लिया गया है और उन्होंने भाषा नीति के कार्यान्वयन और आगे की राह सुझाने के लिए शिक्षाविद् नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की भी घोषणा की। राज ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “लोग 150 से 200 साल पुरानी हिंदी भाषा को उस मराठी से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इतिहास 3,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह अस्वीकार्य है और मैं यह होने नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसी भाषाई विविधता वाले देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित करने की वैधता पर सवाल उठाया। मनसे प्रमुख ने कहा, “हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है जिसे दूसरे राज्यों पर थोपा जाए। इस तरह की जबरदस्ती ठीक नहीं है।

सम्पादकीय

आतंक के विरुद्ध भारत की दृढ़ता, नहीं कर सकते आतंकी हमलों की अनदेखी

चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन-एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आतंक के खिलाफ भारत की दृढ़ता के लिए याद किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख तो नहीं था, उलटे बलूचिस्तान का संदर्भ जोड़ दिया गया था। भारत का यह रुख पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कायम उसके रवैये के अनुरूप ही है कि आतंक के साथ अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर भारत किसी मंच पर इसे लेकर अलग-थलग भी पड़ जाए तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं। इससे पहले आपरेशन सिंदूर के बाद भी विभिन्न देशों में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से भी भारत ने वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान के आतंकी वेहेरे को बेमकाब करने का जोरदार अभियान चलाया था। एससीओ के मंच पर भी भारत ने उसी नीति की निरंतरता को प्रदर्शित किया। मूल रूप से चीन के वर्चस्व वाले एससीओ का भारत काफी समय बाद सदस्य बना है। पाकिस्तानी भी इसका सदस्य है। इस समूह के प्रमुख उद्देश्यों में से एक यह भी है कि आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए आधार तैयार करने की भूमिका निभाएगा, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली उसके चरित्र से मेल नहीं खाती। समय के साथ इस संगठन में चीन का वर्चस्व और बढ़ता गया है। इसका एक कारण बदले हुए वैश्विक समीकरणों में रूस पर लगे तमाम प्रतिबंध भी हैं, जिनके चलते मास्को की बीजिंग पर निर्भरता बढ़ी है। अन्धत्वा रूस भी इस सल्ले में एक संतुलक की भूमिका निभाता रहा है। बढ़ते दबदबे का लाभ चीन अपने निहित स्वार्थों को साधने में कर रहा है। पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन इसकी पुष्टि करता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि आतंकवाद को लेकर चीन कई मौकों पर पाकिस्तान की ढाल बना है और ऐसा ही एक प्रयास उसने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी किया। यह इससे स्पष्ट झलकता है कि पहलगाम के जिस आतंकी हमले की दुनिया भर में कई भर्त्सना हुई उसका उल्लेख तक एससीओ दस्तावेज में नहीं किया गया। उलटें उस बलूचिस्तान का प्रसंग जोड़ा गया जहां पाकिस्तानी सेना द्वारा स्थानीय लोगों का बर्बरता से किया जा रहा दमन मानवीय उत्पीड़न के नए रिकार्ड बना रहा है। पहलगाम का संदर्भ हटाकर और बलूचिस्तान का मुद्दा जोड़ने की यह काव्यवाद भारत को असहज करने के लिए ही की गई और ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर से किनारा करके बिल्कुल सही किया। असहमति के इस संदेश की गूंज दुनिया भर में सुनी जाएगी। चीन और पाकिस्तान को लेकर अक्कर कहा जाता है कि भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए अपनी तैयारी करनी होगी, लेकिन देखा जाए तो यह दोहरा नहीं, बल्कि एक ही मोर्चा है। हम चीन और पाकिस्तान को अलग करके नहीं देख सकते। चीन का पाकिस्तान प्रेम इस कदर बढ़ चुका है कि उसके लिए वह भी कदम उठाने को तैयार दिखता है। एससीओ की हालिया सम्मेलन की ही बात करें तो किसी भी संगठन में चेयर या प्रमुख की भूमिका वाले देश का एक दायित्व यह भी होता है कि वह समूह के संस्र्भ आए एजेंडे पर सहमति बनाए। यदि सहमति न भी बना पाए तो ऐसा करने के लिए प्रयासरत तो दिखना चाहिए, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक से जुड़े संयुक्त बयान के मामले में चीन ने ऐसी कोई कोशिश तक नहीं की। दोनों देशों की यह मिलिभगत वह दुरिभसति दर्शाती है, जिसका भारत को समय रहते कोई तोड़ खोजना होगा। पाकिस्तान के साथ निपटना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे मिलता चीन का साथ इस चुनौती को और विफल बनाता जाएगा। भारत और चीन के संबंधों में भी लंबे समय से तल्कली हावी रही है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच वार्ता से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कुछ सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति ने ही दोनों देशों को परस्पर हितों की पूर्ति के लिए साथ आने के लिए कुछ हद तक प्रेरित किया है। परिणामस्वरूप संबंधों में कुछ सहजता का भाव बनता दिखा है। कैलास-मानसरोवर यात्रा भी पांच साल बाद फिर से आरंभ हुई है। इस सबके बावजूद इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान का पहलू चीन के साथ संबंधों में सदैव एक रोड़ा बना रहेगा। चीन अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत को भाव तो देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं।

जस्टिस यशवंत वर्मा हाजिर हों!

वारेन हेस्टिंग्स को खिलाफ महाभियोग (1788-1795) की बहस में सांसद और वकील एडमंड बर्क ने कहा था— सत्य, न्याय और इंसानि के लिए सत्य और न्याय के मार्ग पर जो राष्ट्र चलता है, वही महान है। बेहद गंभीर आरोपों और पर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद ब्रिटिश संसद ने हेस्टिंग्स को बेकसूर माना और कंपनी ने उन्हें 4,000 पौंड सालाना पेंशन भी दी। शायद सत्ता अपने नाइले सपूतों के बचाव में ऐसे ही न्याय के नाटक-नौटंकी करती रही है। 4 मार्च, 2025 को दिल्ली के एक बंगले के स्टोर रूम में अधी रात आग लगने से धुंआ उठने लगा। आग में जलते नोटों के ताप से कांच की बोतलें टूटने और शराब बहने से आग और भड़क उठी। आग में शराब ने धीरे से भी अधिक खतरनाक काम किया। बंगला दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमंडल पर शावंत वर्मा को आवंटित था। दमकल, पुलिस आई, आग बुझाई, वीडियो बनाई और जले-अधजले या बचे करोड़ों रुपये और शराब की बोतलों को धूँ की या यूँ छोड़ चली गई। कोई पंचनामा (एफआइआर) या बरामदगी नहीं थी। गई। घटना के समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। अगले दिन आए तो घटनास्थल पर शेष-अशेष कुछ न था। विश्वासपात्र नविक और अन्य सेवकों ने सब साफ-सफाई कर दी। मीडिया में हफ्ते भर के कोर्ट खबर नहीं। कैश कांड की जानकारी गोपनीयता और संवेदनशीलता के घूंघट में उच्चाधिकारियों, न्यायाधीशों के बीच घुमती रही। अदालत के कमलियाओं में धुंआ, धूल और धुंध...खामोशी का षड्यंत्र गहराता रहा, अटकलों का बाजार गर्माता गया। कुछ पत्रकारों ने पर्दा हटाना शुरू किया तो पहले राज साहब को न्यायिक कार्य न करने के निर्देश आए फिर इलाहाबाद वापस आने के आदेश जारी हुए। कैश कांड की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने की सिफारिश करके गैर संसद के पाले में लुटका दी और खुद सेवानिवृत्त हो गए।

न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अधिकांश दस्तावेज (जैसे रिपोर्ट के अलावा) सार्वजनिक करने पड़े। न जाने कैसे जांच रिपोर्ट बाद में सार्वजनिक हो गई। जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस फाल्गुनिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनु शिवरमन शामिल थे। फलहाल महाभियोग की पेचीदा प्रक्रिया चलाने या न चलाने के मुद्दे परलहाल विवाद-विवाद, सहमति-असहमति की राजनीति के इर्द-गिर्द ही वरिष्ठ न्यायावलीकों द्वारा सार्वजनिक रूप से कानूनी तर्क-वितर्क खेले जा रहे हैं। कानून मंत्री सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने में प्रयासरत हैं। एक ओर न्यायपालिका में आमजन की आस्था बचाए रखने के लिए और संसद को न्याय सामले पर बहस करने, वोट देने और अभियोग सिद्ध करने की दुरुसाधन प्रजटिलता से बचाने के लिए यह सलाह दी जा रही है कि जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे दें, ताकि न्यायपालिका और संसद का धर्मसंकट से बचाव हो सके। दूसरी ओर उपलब्ध तथ्यों पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सांसदों में वकील और वकीलों में सांसदों में जाने-पहचाने लोग रहे रोज नया रास्ता तलाश-तराश रहे हैं। कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं, पर यथार्थ यह है कि न्याय मंदिरों के विशाल प्रांगण में भी भ्रष्टाचार के विष-वृक्ष अग्रस्थिति रूप से फलते-फूलते रहे हैं। यौन शोषण के अधिक आर्थिक पारिवर्ती तक के आरोपों में अक्सर लीपापोती होती रही और अधिक हुआ तो न्यायाधीशों से इस्तीफा लेकर बाइज्जत मुक्त कर दिया गया।

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते राहुल गांधी

डॉ. आशीष वशिष्ठ

नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में नए नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में करारी पराजय के बाद कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने चीखना शुरू कर दिया था— 'इईदीपम में भूत है', जो भाजपा को विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान बोस्टन में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए, चुनाव पर बड़े संभावनाएं उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग का प्रभुत्व माइज्ड है। ताजा संसर्ग राहुल गांधी ने 'मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र' शीर्षक से 7 जून को एक लेख किया। ये कई अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और भाजपा ने सुनियोजित तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया हो या फिर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया हो। वो आदत अक्सर ऐसा करते रहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करता है जिसे संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा और संसदीय निर्वाचित निकायों के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने का दायित्व दिया गया है। यह लक्ष्य संस्था न तो कार्यपालिका के अधीन है और न ही किसी राजनैतिक दबाव में काम करती है। भारतीय निर्वाचन आयोग केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं बल्कि विवाद-निराकरण और मतदाता-विश्वास निर्माण की भी जिम्मेदारी निभाता है। आयोग मतदाता प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए कई स्तर पर काम करता है। राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता के कुछ भी बयान देते हैं, पर तर्क और तथ्य की कमी होती है। इससे समाज में भ्रम फैलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। विदेशी धरती पर जाकर वो देश का अपमान, मोदी सरकार की आलोचना और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई अवसर चूकते नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि श्मारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा (ब्रोकेन) हुआ था, अब यह लड़



है। है। है। उनका यह कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर ही सवाल उठता है। खासकर तब जब भारत में लगातार चुनाव होते रहे हैं और सरकारें बदलती रहीं हैं। बीते 10-11 वर्षों में देश में कई ऐसी सरकारें बनी हैं, जिसे बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस को मौका मिला है। मतलब, अगर नतीजे राहुल और उनकी पार्टी के लिए अच्छे रहें तो लोकतंत्र ठीक है और नहीं तो वह श्रोकें हो जाता है।

सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में शफूल स्कूल एग्राॅल्टर हो रहा है। उन्होंने संस्थाओं की निष्पत्ता पर संदेह जताया। मई 2022 में लंदन में श्वाइडियाज फॉर इंडिया समेलन में राहुल ने कहा कि भारत की संस्थाएं श्रपरीजीव बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्डीप स्टेट्स (सीबीआई, ईडी) भारत को चबा रहा है। यहां श्डीप स्टेट्स का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यहां श्डीप स्टेट्स का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र से भी कर दी। 2017 में ही अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वह नहीं रहा जहां हर कोई कुछ भी कह सकता है। उन्होंने विदेशी की ढारती पर भारत में श्फी स्पीचर की स्थिति पर संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में सहनशीलता खत्म हो गई है।

बाबकि, हकीकत ये है कि राहुल गांधी संसद से लेकर बाहर तक जगह जगह जी जी में आता है, बयान देते रहते हैं और सरकार को छोड़ दें, शाशयद ही कोई संस्थापनिक संस्था बची हो, जिस पर उन्होंने निशाना बना न सथा हो। राहुल गांधी यह क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही वे चुनाव संपन्न करवाए हैं, जिनके दम पर वह आज पिषक्ष परिवार के तीन-तीन सदस्य इन्नी चुनावी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संसद में मौजूद हैं। यही की संवेधनात्मक संस्थाओं ने उन्हें इतनी राहत दी हुई है कि नेशनल हेराल्ड के संसद में गंभीर आरोपों के बावजूद वो और उनका मां सोनिया गांधी को जमानत मिली हुई है। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक तौर पर भले ही भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का चलन बन गया हो लेकिन भारत के चुनाव आयोग की प्रशांसा केवल देश के भीतर ही नहीं संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों और कई विदेशी सरकारों द्वारा भी की गई है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के 2020 के एक अध्ययन में भारत के चुनाव आयोग को 'वन ऑफ द मॉस्ट रोबस्ट इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली' (विश्व स्तर पर सबसे मजबूत चुनावी संस्थाओं में से एक) कहा गया। यही नवों, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि तत्कनीक, प्रशिक्षण और जनता की भागीदारी के माध्यम से एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव है। बीती कई को बहुजन समाज पार्टी की

ताजा संदर्भ राहुल गांधी ने 'मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र' शीर्षक से 7 जून को एक लेख लिखा। ये कई अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और भाजपा ने सुनियोजित तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठया हो या फिर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया हो। वो आदतन अक्सर ऐसा करते रहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करता है जिसे संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा और सभी नेर्वाचित निकायों के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मंजून कराने का दायित्व दिया गया है। यह संस्था न तो कार्यपालिका के अधीन है और न ही किसी राजनीतिक दबाव में काम करती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने से चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया था। यह वाचनीय निर्वाचन आयोग की उषा नई पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों को सीधे ठीक पर मजबूत और पारदर्शी बनाना है। चुनाव आयोग अब तक देशभर में कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में अब तक 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से लिखित में तथ्यों की मांग की और चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया है और अब यह दायित्व बनता है कि आरोप लगाने वाले नेता उन्हें उचित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करें। हालांकि राहुल गांधी के पूर्व रिकार्ड के हिस्सा से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अभिषेक सिंघवी, विवेक तन्हा जैसे बड़े वकीलों और पार्टी के अन्य नेताओं को रखा हुआ है। राहुल गांधी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। अगर एजेंसी आरोपों को जवाब देना चाहती है तो वह सुनना उनका काम नहीं है। कर्मोपेक्षा ऐसा ही आचरण उनका संसद में भी है। असल में, राहुल गांधी आरोप लगाकर, सामने वाले का पक्ष या जवाब सुनने की बजाय कोई नया आरोप लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। तथ्य और तर्क से

उनका कोई लेना देना नहीं रहता । तथ्य यह भी है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की ओर से इसी तरह के मुद्दे उठाए गए थे । आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी को एक विस्तृत जवाब दिया था, जिसकी प्रति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है । इससे यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी इस अध्याय का पटाक्षेप नहीं चाहते हैं । उनकी पार्टी इस मामले को जिंदा रखना चाहती है ताकि आगे के चुनाव नतीजों को सुविधा को हिसाब से संदिग्ध बनाया जा सके । चुनाव आयोग ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव, मीडिया उन्माद या सार्वजनिक सनसनी से परे केवल संविधान और मर्यादा के प्रति जवाबदेह है । इसलिए आज जरूरत है कि हम आलोचना करें लेकिन तथ्यों पर करें । सवाल उठाएँ लेकिन समाधान के साथ और सबसे अहम कि लोकतंत्र की मजबूती, सतत निगरानी और निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनायी गयी संस्थाओं का सम्मान बनाए रखें ताकि आमजनों की लोकतंत्र और उनकी संस्थाओं के प्रति आदर का भाव बना रहे । उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग कोकरोमाइज्ड है । ताजा संदर्भ राहुल गांधी ने 'मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र' शीर्षक से 7 जून को लेख लिखा । ये कई अखबारों में छपा । इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और भाजपा ने सुप्रीमकोर्ट तक से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया ।

**बीज पर काम करें,
तो फल अपने आप
आपको चौंका देंगे**

प्राचार्यण हेल्थ के चेयरमैन कार्यकारी निदेशक डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी ने काफी पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत पहला ऐसा देश बनने को तैयार है, जहां स्वास्थ्य देखभाल व पैसा अलग-अलग होगा और ये बदलाव अगले 5 से 10 वर्ष में ही हो जाएगा। इस दावे के समर्थन में डॉ. शेट्टी ने तीन बड़े अर्थव्यवस्था-भारत, अमेरिका व चीन में मोतियाबिंद सर्जरी की तुलना की उन्होंने कहा, 'अमेरिका में सालाना 35 लाख मोतियाबिंद सर्जरी होती हैं। आबादी के लिहाज से चीन का इसकी पांच गुना सर्जरी करनी चाहिये पर वह सिर्फ 32 लाख ही करता है जबकि भारत में 85 लाख सर्जरी सालाना होती हैं, जो अमेरिका, चीन और बहुत से यूरोपीय देशों का मिलाकर भी अधिक है। शेट्टी व अनुसार ये उन उद्यमी चिकित्सकों के कारण संभव हुआ, जिन्होंने स्वतंत्र क्लिनिक खोले। इससे सर्जरी का खर्च घटा। उन्होंने गर्व से कहा 'भारत अपने स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे में बदलाव कर रहा है। जो हमने हासिल किया, वो कोई और देश नहीं कर सकता।' डॉ. शेट्टी ने पहले के एक्सपर्ट में कहा था, 'नज़ी क्षेत्र में बहुत महंगी होती जा रही चिकित्सा शिक्षा के कारण हम आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों में से बहुत से जादुई हाथ छोटे जा रहे हैं।' उनका मतलब था कि भविष्य के ऐसे बहुत से प्रतिभावान डॉक्टर हैं, जो मेडिसिन में योगदान दे सकते हैं, पर महंगी पढ़ाई के कारण वे अवसर खो रहे हैं। डॉ. शेट्टी के वो दोनों कथन मुझे तब याद आए, जब मैंने हाल ही में सुना कि कैसे उत्तरप्रदेश के सर्वोदय स्कूल की 25 से से 12 छात्राओं ने नीट परीक्षा पास की है, जिसका परिणाम इसी सप्ताह जारी हुआ है यहां उन छात्राओं की कहानी बताता हूँ। प्रिंसी खेतियार मजदूर की बेटी हैं, पूजा रंजन सोमनद्र के किसान की बेटी हैं, वहीं कोशाब की श्वेता साइलिक का सीट कवर बेचने वाले परिवार में पली-बढ़ीं। उनका सपना सरकारी स्कूल से ऑफिशियल कुछ भी नहीं था और वे हाँसिल्टन बेड्स में बीच इधर-उधर भागती महिला डॉक्टरों को दूर से देखकर सिरफ अचरज करती थीं। एतन पहनकर गले में स्टेथोस्कोपी लगाए देखकर की कल्पना मात्र से ही वह डर जाती थीं। पर अब ऐसा नहीं है। अपने स्कूल की नौ अन्य छात्राओं समेत इन तीनों ने इस वर्ष नीट परीक्षा पास कर ली है। यूपी के मिर्जापुर

बाढजनित हादसों में कब तक होती रहेगी जन-धन की हानि



योगेन्द्र योगी

देश में सरकारी मशीनरी की तंत्रा तंत्र बंग होती है, जबकोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र जागने के लिए बड़े हादसों की इंतजार में रहता है। पहले जरूर हादसों से सबक सीखने की जगह सरकारी महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है जिम्मेदारी का अभाव। यदि यह जिम्मेदारी तंत्र कर लेती जाए कि किसी तरह के हादसों के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हादसा होने की सूख में उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तब भी हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरुआत है। हर साल मानसून के दौरान देश में बाढ़ जनित हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत होती है। भारी बारिश से देश को अरबों रुपयों की सम्पत्ति नुकसान होता है। जन-धन की इस हानि की किसी जिम्मेदारी तय नहीं है। आखिर कौन हर साल होने वाले ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है? हादसा होने के बाद सिर्फ लकीर पीटी जाती है। ऐसे उपाय नहीं किए जाते कि हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या फिर इनकी संख्या में कमी लाई जा सके। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) के नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी बाकी है, जो इतिहास में भारत का सबसे गर्म साल रहा

है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई हैं, या दोनों ही बातें हो रही हैं। 1970 से 2021 तक का डेटा दिखाता है कि इस समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़, सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013–2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। जिससे देखा जा सकता है कि पिछले दशक में चक्रवातों के अनुसार, भारत में बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहाँ संपत्तियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ की संख्या ज्यादा है। जिससे एक प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों और अध्ययनों के प्रकाशित करती है। जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ में सुंदरी बंदरगाह, जैसे काला और मुंदरा बंदरगाह, बंद हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। दिसंबर 2023 में चक्रवात मिफांग के चलते चेन्नई क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़े नुकसान हुए। इसके अलावा जून-जुलाई 2023 में उत्तरी भारत और सिक्किम में आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को बुरी तरह

प्रभावित किया। स्विस् रे के विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत में गर्मी का मौसम (जून से सितंबर) और पूर्वीतम मौसम (अक्टूबर से दिसंबर) भारी बारिश लाते हैं, जिससे गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कुछ बड़ी घटनाओं में 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू और कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल की बाढ़ शामिल हैं। साल 2023 में उत्तर भारत की बाढ़ ने भी एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है कि नुकसान में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख है। बढ़ते तापमान से चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ता निर्माण और आबादी आपदा के समय अधिक नुकसान का कारण बनते हैं। बाढ़ और सूखे आपदाओं से सड़कों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। इससे ना केवल आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं बल्कि यह लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। कुदरती आपदाओं के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और फिर से निर्माण में भारी खर्च आता है। प्राकृतिक आपदाओं से भारत के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित

हैं। तटीय राज्य, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल अक्सर चक्रवात और समुद्री तूफानों का सामना करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गंगा के मैदान हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राजस्थान और गुजरात बार-बार सूखे का सामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के लिए संवेदनशील हैं। साथ ही, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहर बाढ़ और जलभराव के लिए अधिक संवेदनशील हैं। वर्ष 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ भारत की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से हैं। इनसे क्रमशः 5.3 अरब डॉलर और 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट कहती है कि इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बेहतर योजना और आपदा प्रबंधन की सख्त जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। रिसर्च के मुताबिक भारत को आपदा प्रबंधन और तैयारी के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो आपदाओं का सामना कर सके। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रिसर्च की रिपोर्ट में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। जैसे कि डेटा और प्रभावित केंद्रों की पहचान कर संवेदनशील क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा बनाना होगा। आधुनिक तकनीकों और डेटा का इस्तेमाल कर नुकसान का सटीक आकलन किया जाए। ऐसी बीमा योजनाएं तैयार की जाएं, जो अधिक लोगों तक पहुंच सकें और प्राकृतिक आपदाओं के बाद

वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकें।
फरवरी 2021 में उत्तराखंड में एक हिमपाव के फटने के कारण बर्फ, हिम और मलबे का स्खलन होने से व्यापक श्वेतशैल फलण्ड उत्पन्न हुआ। भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति के रूप में 1,805 करोड़ रुपय मूल्य की हानि का कारण बनती है। सवाल यह है कि आखिर देश के लोग बाढ़जनित आपदाओं की मार कब तक झेलते रहेंगे। हर साल होने वाली मौतों और हजारों करोड़ की सम्पत्ति की बर्बाद अखिर कब थमेगी। सिर्फ प्रकृति को दोष से देने से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लापरवाही की बहानेबाजी का यह सिस्त्रिला तब तक चलता रहेगा, जब तक सजा का कठोर प्रावधान नहीं होगा। 1970 से 2021 तक का डेटा दिखाता है कि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं, जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़, या सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013-2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। रिसर्च के की रिपोर्ट के अनुसार, ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संसियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ की संख्या ज्यादा है। रिसर्च के एक प्रमुख पुर्बोक्ता कंपनी है,।

लेला या छात्राएँ खासतौर पर नौती के लिए जाँचेंगे भी शामिल होना चाहेंगे। वहां नीट-कॉलेजों के लिए दाखिलनामा देने वाली 39 छात्राओं में से 25 न परीक्षा दी और 12 उत्तीर्ण हुई। इस सफलता से प्रेरित होकर समाज कल्याण विभाग के 'सेन्टर फॉर एक्सीलेंस' को पूरे यूपी के अन्य सर्वोदय विद्यालयों में भी शुरू किया जा रहा है, यूपी में ऐसे स्कूलों की संख्या लगभग 100 है। मैं जयपुर व शेपिंग प्यूचर नाम के एक संगठन के बारे में जानता हूँ, जो आर्थिक तौर पर कमजोर ऐसे सैकड़ों बच्चों की सहायता करता है, बशर्तें व बच्चे मेधावी हों और भविष्य के भारत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकें। की योग्यता रखते हों। इन युवा मे पावी विभागों को जो चाहिए, वह हैं। सीखने की तकनीक में जरा सा अंतर प्रोत्साहन और थोड़ी सी वित्तीय सहायता। और फिर, जैसा कि डी.रोशेटी ने कहा, भारत को विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया के किसी भी देश को मात देने से कोई नहीं रोक सकता। यह तर्क कि हम जैसे लोग भी अपने आपसपा ऐसे प्रतिभाशाली फंडाओं को पहचान सकते हैं। फंडा यह है कि यदि हम बीजों पर काम करेंगे, मगर मतलब कि आर्थिक रूप से सबसे घनिष्ठता पादान पर बैठें गये बच्चों पर, तो उनमें से उपजाऊआ बीज रूपी बच्चे प्रकाश की ओर बढ़ेंगे और संबंधित क्षेत्र में मिसाल काय करेंगे। उन्हा मतलब था कि भुषिष्ठा के ऐसे बहुत से प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं, जो मेडिसिन में योगदान दे सकते हैं, पर मर्गरी पढ़ाई के कारण वे अवसर खो रहे हैं। जै. शोर्टी के व दोनों कथन मुझे तब याद आए, जज मैंने हाल ही में सुना कि कैसे उत्तरप्रदेश के सवईय फूल की 25 में से 12 छात्राओं ने नीट परीक्षा पास की है,

ग्राम संघ अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा ने जिलाधिकारी बलराम पुर को सम्बोधित एक ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी उतरौला को सौंपा।



उतरौला बलरामपुर सोमवार को ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक तकनीकी सहायक संघ संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने प्रधान संघ अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी बलरामपुर को सम्बो धित एक ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी उतरौला को सौंपा।

दिए गए ज्ञापन में कहा है कि विकास खण्ड पंचपेड़वा अन्तर्गत ग्राम पंचायत विशुनपुर टन टनवा में मनरेगा योज नान्तर्गत अन्तर्गत निर्मि त 03 तालाब के सापेक्ष की गई जांच में

रुस्तम नगर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी उतरौला को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा।



उतरौला बलरामपुर राप्ती नदी के तट पर कटे बंधे के निर्माण को लेकर ग्राम रुस्तम नगर के बाशिंदों ने एक शिकायती पत्र उपजिला धिाकारी उतरौला को सौंपा। नाराज ग्रामीणों ने दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उक्त गांव में बाढ़ से बचाव हेतु वर्ष 2010 बंधा बनाया गया था, जो पिछले साल बाढ़ के

यूपीएसएसएससी परीक्षा में बिजली निजीकरण पर आया सवाल,



लखनऊ (संवाददाता)।उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के जुनियर अर्रिस्टेंट पद की लिखित परीक्षा में बिजली निजीकरण से संबंधित भी एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि

पेशी से एक दिन पहले युवक को घर से निकालकर सीने पर मारी गोली, मौत



लखनऊ (संवाददाता)।बहराइच में जमीन के विवाद में एक युवाक को घर से निकालकर गोली मार दी। सोमवार को विवाद की पेशी थी। उसके एक दिन पहले ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।जमीन के विवाद में विशेष्वरगंज क्षेत्र के चंदईपुर निवासी योगेश चौबे (28) को उनके पड़ोसियों ने रविवार देर शाम घर से निकालकर गोली मार दी।

परिजन गंभीर हालत में उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।जितेंद्र चौबे ने बताया कि उनका पड़ोसियों से जमीन का विवाद चल रहा है। रविवार शाम वह धान की रोपाईं करवा रहे थे। चचेरे भाई

दोषी पाये गये ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक, जे०ई०,ए०पी०ओ० के विरुद्ध जिला प्रशासन के निर्देश पर खण्ड विकास अधिकारी महोदय,पंचपेड़वा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। जिसके क्रम में सभी लोग जेल चले गये, किन्तु मनरेगा अन्तर्गत उस तालाब पर लगभग 38 लाख रुपये के भुगतान पर तत्कालीन खण्डविकास अधिकारी धनन्जय सिंह को जिला प्रशासन के द्वारा बचा लिया गया जब कि भुगतान तत्का लीन विकास अधिकारी धनन्जय सिंह के डोंगल द्वारा किया

गया। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। तत्का लीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट जिला प्रशासन के द्वारा अविलम्ब दर्ज कराया जाये। ग्राम पंचायत बैज पुर विकास खण्ड बल रामपुर में पंचायत भवन निर्माण कार्य में हुई अनियमितता पर दोषि यों के खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जबकि दुरुप योग की गई धनराशि की वसूली दोषी कर्म चारियोंध प्रधान से सीधे या उनके वेतन से की जा सकती थी। इसी क्रम में दिनांक 27.06. 2025 को विभागीय अधिकारियों के अभि योजन मे स्वीकृत के बगैर महिला कर्मचारी श्रीमती आरती रावत जिसके गोद में 04 माह की बच्ची है, एवं ग्राम प्रधान अरुण सिंह को अमानवीय तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, पुलिस प्रशा सन के द्वारा किया गया उक्त कृत्य घोर निन्दनी य है। यदि जिला प्रशासन न में मानवीय संवेदना होती तो उस महिला कर्मचारी को जेल जाने से बचाया जा सकता था, क्योंकि कारागार में निरुद्ध करने जैसा गम्भीर अपराध उनके द्वारा नहीं किया गया था। तत्काल मुकदमा वापस लेकर उपरोक्त की रिहाई कराया जाये।

जिले के अधिकांशग्रामों में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन डालने एवं गांव में

खोदी गईसड़कों का मरम्मत नहीं हुआ है एवं विकास खण्ड बल रामपुर के ग्राम पंचायत चूल्हा भारी में पानी की टंकी फट गई थी प्रशास न के द्वारा मुकदमा की कोई कार्यवाही नहीं की गई, सड़क व गलियां खोदी मरम्मत का कार्य नहीं कर रहे हैं। जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई जाए। जिला प्रशा सन के द्वारा उपरोक्त पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में 252 रूपये की मजदूरी होने के कारण मजदूर कार्य करने को तैयार नहीं है, इस कारण हम सभी काफी परेशान हैं तथा हम सभी से अनुचित शोषण व धन मांग न पूरी कर पाने के कारण अधि ाकारियों के द्वारा परेशान एवं प्रताड़ित होने की वजह से हम लोग मनरेगा का कार्य नहीं करेंगे, एवं वर्तमान में भी समस्त कार्य बन्द रखेंगे। ग्राम जिला प्रशासन न में मानवीय संवेदना द्वारा सोंपे गये लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्षा रोपण के पश्चात कई कारणों से पेड़ों की जैसा गम्भीर अपराध उनके द्वारा नहीं किया गया था। तत्काल मुकदमा वापस लेकर उपरोक्त की रिहाई कराया जाये।

दस मोहर्रम के जुलूस में एम्बुलेस चिकित्सा सेवा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।



उतरौला बलरामपुर दस मोहर्रम का जुलूस ए आशूरा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला के द्वारा

यूपी बोर्ड : इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की लिखित परीक्षा १९ जुलाई को, ४६ हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

लखनऊ (संवाददाता)। यूपी बोर्ड की ओर से वर्ष–2025 की हाईस्कूल इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट की लिखित परीक्षा 19 जुलाई को आयोजित की गई है। परीक्षा के लिए 46,360 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। इस दौरान वाइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी के कैमरे और राउटर क्रियाशील रहेंगे। हाईस्कूल इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा आनी चाहिए।बिजलीकर्मियों की समा आद्य झांसी में पूर्वांचल दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में दो जुलाई हो होने वाले प्रदर्शन और जेल भरी अभियान की तैयारी शुरु हो गई है।

पूरे प्रदेश में मानसून का असर, ३0 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, बढ़ा नदियों का जलस्तर

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तरप्रदेश में मानसून की चाल कुछ दिनों तक मद्धिम रहने के बाद, रविवार से इसकी जोरदार वापसी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसूनी ट्रफ लाइन खिसक कर मध्य यूपी की तरफ आ रही है। इसके असर से 30 जून से 1 जुलाई के बीच पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। बारिश के दिन के पारे में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आरूपी और गर्मी से तात्कालिक तौर पर राहत मिलेगी। सोमवार के दौरान सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शामली समेत सात जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।

वहीं सोमवार को लगभग 35 जिलों में भारी बारिश और 65 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। रविवार को देवरिया, बागपत, संभल आदि को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम टॉलरेंस नीतिश्श्श् के बारे में कहा कि यूपी अब देश का सबसे सुरक्षित राज्य है और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ।

भी नहीं करेंगे।ग्राम पंचायतों को प्रत्येक अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के कारण तथा ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव सहित अन्य कर्मचारियों को दुर्दान्त अपराधी की तरह अपमानित करके जेल भेजे जाने के कार ण कारागार में निरुद्ध व्यक्तियों के रिहाई तक हम सभी कोई कार्य नहीं करेंगे। महोदय शासन के आदेश संख्या –1350६48०7.02.2022–296६ मनरेगा 2013 दिनांक 22.08.2022 में बिन्दु संख्या –3 के पैरा तीन में मनरेगा हेतु ग्राम पंचा यतों को दिये गयेसमस्त अधिकार को जान बूझ कर भ्रष्टाचार के उद्देश्य से लागू न करने से प्राय: ग्राम पंचायत में मनरेगा की विसंगतियां उत्पन्न होती है, इसे तत्काल उक्त शासनादेश को लागू किया जाये,अन्य था इसी दशा में ग्राम पंचायतों पर कोई कार्यवाही न की जाये।मनरेगा एक मांग आधा रित योजना है। जनपद अधिकारियों एवं विका स खण्ड के अधिकारि यों के द्वारा उत्पीड़न एवं शोषण के उद्देश्य से जबरदस्ती लक्ष्य आधा रित योजना बना दिया गया है, जो कि मनरेगा एक्ट का उल्लंघन साबि त हो रहा है एवं मनरेगा में जबरदस्ती कार्य का दबाव कोरोका जाये। प्रत्येक माह सी०एम० डैसबोर्ड के रैंकिंग के नाम पर अधि कारियों के द्वारा शासन को गुम राह करने हेतु जबरन भुगतान करने एवं अन्य फर्जी तरीको से रिपो टिंग करने का

दबाव बनाया जाता है, जिससे शासन के समक्ष सही स्थिति प्रस्तुत नहीं हो पाती है, एवं नियमों के उल्लंघन करने की सम्भावना बनी रहती है, और रैंकिंग के नाम पर दबाव बनाया जाना बन्द किया जाये, विभि न्न शासकीय योजनाओं में उच्चाधिकारियों के द्वारा बिना भू–प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव कराये तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति कराये बिना ही जल्द बाजी में कार्य प्रारम्भ करने का दबाव भी बनाया जाता है। जिससे बाद में इन्ही बिन्दुओं को आधारबना कर विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न किया जाता है। उपरोक्त कार्य ण्णा ली पर तत्काल रोक लगाई जाये।उन्होंने यह भी मांग की है कि उउ रोक्त समस्याओं का निराकरण किया जाये, एवं कारागार में निरुद्ध ग्राम प्रधानों एवं समस्त कर्मचारियों की रिहाई करायी जाये,अन्यथा किसी भी दशा में उप रोक्त समस्त समस्याओं के निराकरण के न होने तक हम सभी अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार पर डटे रहेंगे। इस मौके पर प्रधान बहलोलनिया जी,कर्ताराम यादव, वि जय पाल वर्मा,अवकात अली, विमल कुमारवर्मा गुलाब चन्द ,राधे श्याम मोहम्मद उमर अंसारी, वसी खान्, कुर्बान अली मौहम्मद मुबारक,नाजि या,पार्वती,बिंदु देवी, लक्ष्मी देवी सहित तमा म ग्राम प्रध ान व रोज गार सेवक मौजूद रहे।

लोक जनशक्ति पार्टी के सचिव मोहम्मद उमर के आवास पर एक बैठक की गई।

उतरौला बलरामपुरध्ध विकास खण्ड गैडसा बुजुर्ग अन्तर्गत ग्राम पंचायत इटई रामपुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान प्रत्याशी रेहानउल्लाह खान ने बताया कीहमारे ग्राम सभा में कुल 84 गांव की 25800 जन संख्या है जनसंख्या इसमें अन्तिम दाह संस्कार करने के लिए एक भी अंत्येष्टि स्थल नहीं है, जिस ग्राम सभा के लोगों को अन्तिम दाह संस्कार करने के लिए दर–दर भटकना पड़ता है। बरसात के दिनों में और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में जल भराव के होने से ग्राम सभा के लोगों को कई किलो मीटर दूर ऊंचे स्थान पर दाह संस्कार करने के लिए जाना पड़ता है। पूर्व प्रधान प्रत्याशी रेहानउल्लाह खान ने लोग जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद उमर से मिलकरसरकार से मांग की है कि ग्राम पंचायत इटई रामपुर के ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल का निर्माणकराया जाए जिससे ग्राम सभा के लोगों को अन्तिम संस्कार करने के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर लोजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार लोजपा मेहनौन विधान सभा के अध्यक्ष राम नारायण लोजपा गौरा विधान सभा केअध्यक्ष अम्बिका प्रसाद, लोज पा के नेता कुतुबुल्ला खान,हंसराज,इम्तियाज खान, अकबर अली खां रमजानउल्ला खां सहि त तमाम कार्यकर्ता गण मौजूद रहे।

उपजिलाधिकारी उतरौला ने तटबंध का निरीक्षण कर नहर विभाग के एक्सईएन को बुलाकर निर्देश दिया।

उतरौला बलरामपुर/ विकास खण्ड उतरौला अन्तर्गत ग्राम पंचायत रुस्तम नगर में क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत की मांग ग्रामीणों के द्वारा की गई थी। मांग दृष्टि गत को देखते हुए उपजिलाधिकारी उतरौला राजेन्द्र बहादुर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान सरयू नहर के एक्सईएन को बुलाकर निर्देश दिया कि अतिशीघ्र तटबंध के गैप को तुरन्त भरवाने का कार्य शुरु करवाया जाए। इसके बावजूद उन्होंने यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अगर तटबंध के अधुरे होने पर और अगर गांव में जल प्लावन की स्थिति आई तो विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को शासन को संदर्भित कर विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की जाएगी।

कारोबारी ने पत्नी और बेटी के साथ की आत्महत्या

लखनऊ (संवाददाता)। राज्ाणी लखनऊ में रविवार की रात कपड़ा कारोबारी ने पत्नी और बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। सुबह तीनों की लाशें फ्लेट पर मिलीं। उनके मुंह से झग निकल रहा था। इससे जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार सुबह घरवालों को जानकारी हुई तो घर में चौख पुकार मच गई। पास में रखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के अशरफाबाद की है। यहां के रहने वाले कपड़ा कारोबारी शोभित (48), पत्नी (45) सुचिता और उनकी बेटी ख्याति (16) की मौत हुई है। उनके पास से मिले सुसाइड नोट में कर्ज से परेशान होकर जान देने की बात लिखी गई है। बताया गया कि शोभित राजाजीपुरम में कपड़े की दुकान चलाते थे। सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए हैं।

जलभराव से शिक्षकों व छात्रों में दिक्कत

सीतापुर (संवाददाता)। ग्राम धौरहरा में प्राथमिक विद्यालय जाने वाले मार्ग पर एक माह से गंदा पानी भरा है। आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्राम पंचायत जगमालपुर के धौरहरा प्राथमिक विद्यालय जाने वाले मुख्य मार्ग पर जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण और नालियों का गंदा पानी भर रहा है। जलभराव के चलते लोग वायरल और मलेरिया से पीड़ित हैं। एक जुलाई से शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में विद्यालय के सामने भरा गंदा पानी स्कूल आने वाले नौनिहालों के लिए मुसीबत बनेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य जुनैद ने बताया कि विद्यालय के सामने जलभराव होने के कारण शिक्षकों और बच्चों को आवागमन में परेशानी होगी।

एक करोड़ से पेयजल आपूर्ति का होगा काम

हरदोई (संवाददाता)। नगर में जलनिकासी के लिए दो करोड़ रुपये से आठ नालों को बनवाया जाएगा, जबकि एक करोड़ रुपये से पेयजल आपूर्ति का काम कराया जाएगा। इसी के साथ प्रकाश व्यवस्था के लिए भी खरीदारी होगी। चेयरमैन तबस्सुम की अध्यक्षता में हुई नगर पालिका की बोर्ड बैठक में इन कामों के साथ ही और भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। पालिका समगार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए चेयरमैन ने कहा कि आमजन की सुविधा और सहूलियत के कामों को वरीयता पर कराया जाए। सभासदों ने नोटिस के बाद ध्यान न दिए जाने का कर्मियों पर आरोप लगाया।

उपभोक्ता की दुनिया
साध्य हिन्दी दैनिक
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शारदा प्रसाद पाठक द्वारा शंकर प्रिंटिंग प्रेंस निकट भरत मिलाप चौराहा, नई बाजार भिनगा से मुद्रित तथा ग्राम हब्बामार पोस्ट लिटौला जनपद श्रावस्ती 30५0 से प्रकाशित।
सम्पादक
भगवान दीन पाठक
मो10— 91 94504 54367, 91 9६530 13722
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र श्रावस्ती होगा।

महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कानसगंज, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर,

बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में। मानसून के सक्रिय होते ही अवध में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर मानसून के सक्रिय होने और नेपाल में तेज बारिश से अवध क्षेत्र में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोंडा जिले के करनैलगंज क्षेत्र में सरयू नदी का जलस्तर ३7 सेंटीमीटर बढ़कर खतरे के निशान से मात्र डेढ़ मीटर दूर रह गया है। अवैधकटनगर जिले के कम्हरिया क्षेत्र में सरयू नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है।